साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 09-15 मई 2022, वर्ष-8, अंक-6

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

मुख्यमंत्री ने कहा- आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, देश और प्रदेश में नाम रोशन करो

भोपाल। विशेष संवाददाता

मध्य प्रदेश में सामाजिक बदलाव का जरिया बनी लाड़ली लक्ष्मी योजना के नए संस्करण (2.0) का रविवार को भोपाल के लाल परेड मैदान में लाड़ली लक्ष्मियों से खचाखच भरे मैदान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बेटियां अब बोझ नहीं हैं। जन्म से ही लखपति हैं। अब आइआइटी, आइआइएम सहित अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में पाई के लिए लाड़ली लक्ष्मी की पूरी फीस सरकार भरेगी। कालेज में प्रवेश करने पर सो 12 हजार और पाई पूरी करने पर सो 12 हजार रुपये दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए जो भी जरूरत होगी, अब वो सरकार पूरी करेगी। अब प्रदेश में हर साल दो से 12 मई तक लाड़ली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब 42 लाख 14 हजार लाड़ली लक्ष्मियों को देखता हूं तो लगता है कि मुख्यमंत्री बनना सफल हो गया है। जब मेरी भांजियां के चेहरे पर मुस्कान आती है तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती है।

उच्च शिक्षण संस्थानों में लाड़ली लक्ष्मी के प्रवेश पर पूरी फीस देगी मप्र सरकार

बेटियां अब बोझ नहीं हैं जन्म से ही हैं लखपति

भांजियों के चेहरे पर मुस्कान आती है तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती है

लाड़ली लक्ष्मी सृष्टि नेगी ने दिया स्वागत भाषण

लाड़ली लक्ष्मी सृष्टि नेगी ने स्वागत भाषण में कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि हमारे मामाजी ने लाड़ली लक्ष्मी योजना से हमारे भविष्य को सुरक्षित किया है। समाज में लके और लकियों के भेदभाव को इस योजना ने समाप्त कर दिया है। हमें यह महसूस नहीं होता है कि हम किसी से पीछे हैं। हमारे जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक मामा पूरा ख्याल रखते हैं। लाड़ली उत्सव जनांदोलन के रूप में सामाजिक आंदोलन का माध्यम बनेगा।

योजना का चमत्कार है कि आज एक हजार बेटों पर 956 बेटियां जन्म ले रही

उन्होंने कहा कि नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बन गया, तब विचार आया कि अब तो बेटियों को वरदान बनाया जाए। योजना बनाई और जन्म के समय बचत पत्र देने और शिक्षा प्राप्त करने पर राशि देने की व्यवस्था बनाई। 21 वर्ष की होने पर एक लाख 18 हजार रुपये देने का प्रविधान किया। हमने योजना को पाई से जोा। योजना का चमत्कार है कि आज एक हजार बेटों पर 956 बेटियां जन्म ले रही हैं।

12 पास करके कालेज जाने पर 25 हजार रुपये अलग से

अब योजना के नए संस्करण की शुरुआत कर रहे हैं। बेटियां बें और आगे बे, इसमें कोई बाधा नहीं आने देंगे। डाक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस अधकिारी, वैज्ञानिक, शिक्षक बनने के लिए उच्च शिक्षा हासिल करनी होगी। इसमें जो खर्च आएगा, वो सरकार उठाएगी। 12 पास करके कालेज जाने पर 25 हजार रुपये अलग से देंगे। हमने तुम्हारे के लिए प्रगति के सारे द्वार खोल दिए हैं।

-गाय पालने पर 10,800 रूपए देगी बिहार सरकार देगी

बिहार को भाया मप्र का गौ संरक्षण मॉडल

पटना/भोपाल।

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौ सरक्षण के लिए अनुदान का जो मॉडल अपनाया है उसे देशभर में सराहा जा रहा है। गौरतलब है कि मप्र सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती करने वाले देसी गोपालकों को प्रतिमाह 900 रुपए देने की घोषणा की गई है। अब बिहार भी मप्र के इस मॉडल को लागू करने जा रहा है। बिहार में प्रति गायपालक को 10,800 रुपए देने की योजना बनाई गई है।

गौरतलब है कि देश में खेती की लागत को कम करने एवं रासायनिक खेती से हो रहे नुकसान को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वहीं अब मप्र की तर्ज पर बिहार में भी देसी गायों को संरक्षण दिया जाएगा। अभी बिहार सरकार मप्र मॉडल का अध्ययन करा रही है। सारे तथ्यों पर विचार के बाद गायों के संरक्षण का कोई आदशज़ मॉडल अपनाया जाएगा। यानी की अगर आप भी गौपालक या फिर गौ पालने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी।

गोवंश को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता

वहीं बात करें बिहार में सरकारी गोशालाओं की तो अभी 33 जिलों में केवल 86 सरकारी गोशालाएं मौजूद हैं। इन सभी गोशालाओं का सरकार ने विस्तृत ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही गोशालाओं की भूमि, उसकी स्थिति और पशुओं की संख्या आदि की जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कैमूर, अरवल, बांका, शिवहर और पूणिज़या जिले में अभी एक भी सरकारी गोशाला नहीं है। तो वहीं तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि ज्यादा दूध लेने की होड़ में देसी गायें उपेक्षित हो रही हैं। उनका संरक्षण-संवर्धन के लिए बंद गोशालाओं को शुरू कराने और जरूरत के अनुसार नई गोशाला बनाना जरूरी है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार सीमांचल इलाके में गोवंश की तस्करी हर हाल में रोकेगी। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में गोवंश को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता में है। सरकार पशु चिकित्सकों के खाली पदों को भरने की भी कोशिश में लगी हुई है।

गोपालकों को भी प्रोत्साहित करने की तैयारी

बिहार में गायों के संरक्षण के लिए गोशालाओं के साथ निजी गोपालकों को भी प्रोत्साहित करने की तैयारी है। इस संबंध में उपमुख्यमंत्री व पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने प्रदेश की सभी गोशालाओं के अध्यक्षों और सचिवों की बैठक बुलाई है। बिहार में गोवंश के संरक्षण-संवर्धन के लिए आत्मनिभज़र बिहार सात निश्चय के तहत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

मप्र में हर व्यक्ति को 545 ग्राम की दूध उपलब्धता

मप्र इन दिनों दुधारू प्रदेश बना हुआ है। यहां दूध की नदियां बह रहीं हैं। दूध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान वाले मप्र में अब रिकार्ड दूध उत्पादन की संभावना जताई जा रही है। स्थिति ये है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 545 ग्राम प्रति दिन पर पहुंच गई है। दूध की यह उपलब्धता राष्ट्रीय औसत 405 ग्राम से भी ज्यादा है। प्रदेश में 10 हजार 205 दुग्ध सहकारी समितियां हैं जिनसे दूध का संकलन बढ़ाया गया। हाल ही में गुजरे वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश को यह उपलब्धि प्राप्त होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट जारी होने के बाद ही सही स्थिति सामने आएगी।

पशुधन मिशन ग्रामीण युवाओं को बना रहा उद्यमी

आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में सरकार का फोकस युवाओं को उद्यमी बनाने पर है। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू कर रखी है। इसी में से एक है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। इसके तहत सरकार से आर्थिक सहायता लेकर युवा उद्यमी बन रहे हैं। दरअसल, भारत सरकार का राष्ट्रीय पशुधन मिशन पहले से कहीं ज्यादा लक्ष्य आधारित होकर आत्मनिर्भर भारत में जुटा है। उप-संचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग डॉ. भगवान मंघनानी का कहना है कि ग्रामीण युवा भी उद्यमी बनना चाह रहे हैं। विभाग उन्हें सलाह और तकनीकी समर्थन दे रहा है। कोशिश है कि आवदेनों को समय पर प्रक्रिया में लाकर अनुदान राशि के लिए केंद्र के संबंधित विभाग के पास भेज दिया जाए।

-सिंचाई क्षमता 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य

प्रदेश को पानीदार बनाने के मिशन में जुटे शिवराज

भोपाल। संवाददाता

लगभग डेढ़ दो दशक पहले तक बीमारू और पिछड़े राज्य की श्रेणी में आना वाला मध्यप्रदेश अब विकास की बहार वाला राज्य है। पिछले 17 सालों में विकास की पगडंडियों से होते हुए अब आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप पर प्रदेश चल रहा है। प्रदेश में एक तरफ जहां उद्योगों का जाल बिछाकर विकास के नये आयाम स्थापित किये जा रहे हैं तो वहीं कृषि और किसानों को समृद्ध और समर्थ बनाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मध्यप्रदेश को लगातार 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब सरकार का पूरा फोकस सिंचाई योजनाओं के विस्तार पर है। 2003 में 7.68 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होती थी। आज कुल क्षमता 43 लाख हैक्टेयर से अधिक है। सिंचाई क्षमता को 2025 तक 65 लाख हैक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। केन-बेतवा लिंक परियोजना बुंदलेखंड की तस्वीर तथा तकदीर बदलेगी। इस परियोजना के लिए 44 हजार 605 करोड़ रुपये स्वीकृति किए हैं। 8 हजार करोड़ रुपये की लागत से चिंकी-बोरास बैराज परियोजना नरसिंहपुर-रायसेन एवं सांवेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना खरगोन-इन्दौर के निर्माण कार्य जल्द शुरू होंगे। इनसे 2.12 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। 50 मेगावाट बिजली भी बनेगी।

5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई प्रस्तावित

इन परियोजनाओं के निर्माण से करीब 5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई प्रस्तावित है और करीब 12 हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान है। इनमें से कुछ परियोजनाएं दिसंबर 2022 और कुछ मई 2023 में पूर्ण हो जाएगी, जबकि करीब एक दजज़न 2026 में पूरी कराई जा सकेगी। इनमें से कुछ परियोजनाओं में टेंडर प्रक्रिया चल रही है और कुछ के टेंडर भी हो चुके हैं। अधिकांश परियोजनाओं का काम जून 2023 और दिसंबर 2024 तक पूर्ण कराया जाएगा। ये परियोजनाएं नर्मदा नदी आधारित नहीं हैं। इस कारण 2026 तक 60 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कराने का लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। एसीएस डब्ल्यूआरडी एसएन मिश्रा का कहना है कि 46 नवीन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से अधिकांश के टेंडर हो चुके हैं और कुछ के जल्द हो जाएंगे। इन परियोजनाओं पर तेजी से काम कराया जा रहा है।

कलेक्टर ने जिम्मेदार अधिकारी अधिकारियों को दिए निर्देश

प्राकृतिक खेती किसानों के लिए हो सकती है लाभकारी

मंडला। जावेद अली

प्राकृतिक खेती को जिले में बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासन के द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, आजीविका, कृषि विज्ञान केन्द्र, नाबार्ड एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए ब्लॉकवार जमीन चिन्हित करें। इसी प्रकार ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं एवं प्राकृतिक खेती के महत्व से परिचित हैं उन्हें प्राथमिक रूप से प्राकृतिक खेती से जोड़ें। उन्होंने आजीविका मिशन को निर्देशित किया कि ब्लॉकवार ऐसे सक्रिय स्व-सहायता समूहों को भी चिन्हित करें, जो प्राकृतिक खेती से जुड़ें हैं या इस संबंध में कार्य करने के इच्छुक हैं। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में लगभग एक हजार हेक्टेयर कृषि भूमि का चयन करें। उन्होंने अन्य योजनाओं के साथ प्राकृतिक खेती को समन्वित करते हुए प्राकृतक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए क्लस्टर स्तर पर किसानों का चयन करें। उन्हें प्राकृतिक खेती का महत्व बताएं तथा इससे होने वाले फायदों की जानकारी दें। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे किसान जिनके पास पशुधन पर्याप्त मात्रा में है उन्हें भी प्राकृतिक खेती के लिए चिन्हित करें। कलेक्टर ने कहा कि सक्रिय स्व-सहायता समूहों से भी संपर्क करें। इसी प्रकार कृषक समूह का गठन करते हुए उन्हें प्राकृतिक खेती की जानकारी देने एक्सपोजर विजिट कराएं। कलेक्टर ने कहा कि जिले में प्राकृतिक खेती की कार्ययोजना को फलीभूत करने के लिए जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के साथ समिति बनाएं, जो ब्लॉकवार जमीन चिन्हांकन से लेकर सभी गतिविधियों को संपन्न करें। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती करने के लिए तैयार हो जाते हैं उनका किसान क्रेडिट कार्ड तत्काल बनाएं। उन्हें बीज, एक्सपोजर विजिट तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करें। उन्होंने कहा कि आगामी खरीफ सीजन के पूर्व सभी जरूरी तैयारियां पूरी करते हुए प्राकृतिक खेती के लिए प्रभावी कार्य करें। कलेक्टर ने कहा कि नाबार्ड एवं कृषि विभाग प्राकृतिक खेती की संपूर्ण जानकारी से संबंधित वीडियो बनाएं तथा वर्कशॉप एवं किसान चौपाल के दौरान वीडियो के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करें। बैठक में उन्होंने उद्यानिकी विभाग को भी प्राकृतिक खेती के लिए जिम्मेदारी दी।

किसानों को यौगिक खेती की ओर बढ़ना होगा

कसरावद। आत्मनिर्भर किसान अभियान का लक्ष्य किसानों की दशा सुधारना है। सभी को सात्विक और पौष्टिक अन्ना चाहिए। किसानों को स्थिति सुधारने के लिए यौगिक खेती की ओर बढ़ना होगा। बीजों का शुद्धिकरण करने पर किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आध्यात्मिकता के द्वारा किसानों के संकल्पों का शुद्धिकरण करना होगा। यह बात प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा आत्मनिर्भर किसान अभियान के शुभारंभ अवसर पर गुजरात की ब्रह्माकुमारी जानकी बहन ने कही। कार्यक्रम में शीतल बहन, विधायक व पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव, वरिष्ठ कृषि विज्ञानी घनश्याम कुलमी, कृषि विस्तार अधिकारी पीएस बार्चे, एसडीएम कसरावद संघप्रिय, उद्योगपति कल्याण अग्रवाल आदि मौजूद थे। विधायक यादव ने किसानों को जैविक के साथ-साथ यौगिक खेती अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्र के 80 किसानों को ब्रह्माकुमारी के माउंट आबू तपोवन भूमि पर शाश्वत यौगिक खेती के माडल दिखाने व प्रशिक्षण दिलाने के लिए आश्वस्त किया। शीतल बहन ने कहा कि सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है शाश्वत यौगिक खेती ही है। जैविक खेती मनुष्य को तंदरूस्ती व आयुष्य प्रदान करती है। कृषि विज्ञानी कुलमी ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, रासायनिक खेती के अंतर को स्पष्ट करते हुए किसानों की दिशा व स्थिति वर्तमान की क्या है वह स्पष्ट किया। अतिथियों ने किसानों के लिए यह अभियान को जरूरी बताया और खेती पद्धति के बारे में भी बताया।

10 मई तक चलेगा अभियान

केंद्र की भावना बहन ने बताया कि अभियान में छह मई को झापड़ी, मोगावां, माकड़खेड़ा, चोली, कुम्भ्या, समराज, सात मई को बोरावां, देवला, बामंदी, रेगावां, बालसमुद, ढालखेड़ा, आठ मई को बोथू, डोंगरगांव, मर्दाना, खमलाय, कातोरा, पीपलगोन, नौ मई को बाडल्या, अंबा, राजकोट, मोगावां, भुलगांव, 10 मई को उमरिया, अंदड़, बिटनेरा, बाड़ी, मुलठान, खामखेड़ा में कार्यक्रम किए जाएंगे। कार्यक्रम में देवकन्या बहन, सारिका बहन, पूजा बहन, गीता बहन, नेहा बहन ने मंच पर उपस्थित अतिथियों का बैज, गुलदस्ते, पट्टे के साथ तिलक के साथ स्वागत किया। मनीषा बहन ने अतिथियों का स्वागत भाषण दिया। संचालन श्याम भाई ने किया।

एक साल में 75000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य

किसान शून्य बजट वाली प्राकृतिक खेती को अपनाएं: दर्शन सिंह

छतरपुर। कमलेश पांडेय

भाजपा किसान मोर्चा के तत्वाधान में छतरपुर शहर के नारायणपुरा रोड पर स्थित महाराजा गार्डन में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। उन्हें केन्द्र व प्रदेश सरकार की किसान हितकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देकर प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

सरकार खेती को लाभकारी बनाने प्रयासरत

मुख्य अतिथि किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह ने किसानों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है, जो किसानों के लिए कई योजनाएं चलाकर खेती को लाभ का धंधा बनाने में लगी है। उन्होंने किसानों से शून्य बजट वाली प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्राकृतिक कृषि पद्धति को लेकर एक साल की कार्ययोजना बनाई जा रही है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा संचालित किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सहित विभिन्ना किसान हितैषी योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि इनका लाभ किसानों को मिल रहा है।

सरकार द्वारा किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बाबी राजा गठेवरा ने मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह सहित सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष मलखान सिंह, भाजपा प्रदेश मंत्री ललिता यादव, बड़ामलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह, चंदला विधायक राजेश प्रजापति, किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दिलीप पाटोदिया, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अवनींद्र पटेरिया सहित अन्य पदाधिकारी व भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

पूरी कार्ययोजना से किया जाएगा काम

किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह ने कहा कि प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता है। जहर युक्त भोजन के दुष्प्रभाव से प्राकृतिक खेती ही हमें बचा सकती है। किसानों के हित में काम करने के लिए बनाई गई कार्ययोजना की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा एक साल के अंदर 75000 किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ेगा। प्राकृतिक खेती खाका किसानों के बीच रखते हुए बताया गया कि पुराने जलाशयों के समीप प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा, मृदा परीक्षण व फसल उत्पाद परीक्षण के आधार पर चिन्हित किसानों को विशेष लाभ दिया जाएगा। वर्ष भर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाएगा।

क्या है शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने के लिए योजना

योजना में वर्ष 2021-22 के लिए गत वर्ष की भांति बेसरेट 10 प्रतिशत रखा गया है

किसानों को इस वर्ष भी मिलेगा शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर लोन

भोपाल।

किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक पूँजी निवेश के लिए सस्ती दरों पर सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि किसान बिना किसी आर्थिक समस्या के फसलों का उत्पादन कर सकें। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड एवं अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें मध्यप्रदेश सरकार किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से बिना किसी ब्याज के अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराती है। इसमें किसानों को खरीफ एवं रबी सीजन में फसल उत्पादन के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में वर्ष 2021-22 में सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना को निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के किसानों को इस वर्ष खरीफ एवं रबी सीजन में बिना किसी ब्याज के ऋण मिल सकेगा। योजना में वर्ष 2021-22 के लिए गत वर्ष की भांति बेसरेट 10 प्रतिशत रखा गया है और खरीफ 2021 सीजन की ड्यू डेट 15 अप्रैल, 2022 और रबी 2021-22 की डयू डेट 15 जून, 2022 रखी गई है। गत वर्ष अनुसार निर्धारित बेसरेट 10 प्रतिशत के अधीन खरीफ एवं रबी सीजन में अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिये एक प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत (अतिरिक्त) ब्याज अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा।

पशुपालन के लिए भी मिलेगा बिना किसी ब्याज के ऋण

इससे पूर्व हुई मंत्री परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश सरकार ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग में प्रदेश में पशुपालन गतिविधियों हेतु किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से गाय, भैंस, बकरी, सूकर, मुर्गी पालन हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अधिकतम राशि 2 लाख रूपये की साख सीमा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। पशुपालन गतिविधियों हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज दर से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की योजना के क्रियान्वयन से राज्य में पशुपालक आसानी से आदान खरीद सकेंगे तथा सूदखोरों और बिचौलियों से बचाव होकर पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।

जानिए कैसे करें आवेदन

खेत में तालाब बनवाने के लिए सरकार दे रही 1 लाख

भोपाल।

मध्य प्रदेश सरकार जल संरक्षण और किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए तालाब बनवाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जो किसान अपने खेतों में तालाब निर्माण करवा रहे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य तालाबों के माध्यम से वर्षा का जल संरक्षित कर किसानों को सिंचाई की सुविधा मुहैया कराना है। इसके लिए सरकार ने बलराम तालाब योजना शुरू की है। इस योजना के तहत तालाब खुदवाने वाले को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है।

बलराम तालाब योजना

मध्य प्रदेश में किसानों के सिचाई के उचित संसाधन उपलब्ध कराने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बलराम तालाब योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत जो किसान अपने खेत में तालाब बनवा रहे हैं उसे सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ सिर्फ उसी को मिल रहा है, जिसके खेतों में स्प्रिंकलप या ड्रिप सिंचाई उपकरण लगे हुए हैं। यह योजना कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इसका लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

जानिए कैसे करें आवेदन

बलराम तालाब योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट dbt.mpdage.org पर जाना होगा। जहां पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद बलराम तालाब योजना के फार्म को भरना होगा। इस योजना का लाभ पात्र किसान ही ले पाएंगे। बलराम तालाब योजना की अनुदान राशि कृषि विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

जानिए किसे मिलेगा कितना अनुदान

प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई बलराम तालाब योजना की अनुदान राशि सरकार द्वारा आरक्षित जातियों के आधार पर निर्धारित है। इस योजना में सबसे ज्यादा फायदा 75 फीसदी तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिल रहा है। जो 1 लाख रुपये तक हो सकता है। जबकि सामान्य वर्ग और सीमांत किसानों को 40 फीसदी तक अनुदान राशि दी जा रही है, जो अधिकतम 80 हजार रुपये तक निर्धारित है।

अब घर बैठे किसान ऑनलाइन ले सकेंगे भू-अधिकार ऋण पुस्तिका

भोपाल।

किसानों को अक्सर अपने भूमि सम्बंधित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सरकारी दफतरों के चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों को होने वाली इस परेशानी से बचाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने सभी भूमि दस्तावेज को ऑनलाइन कर दिया है। जिसे किसान आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। मध्यप्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग ई-तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, ताकि किसानों एवं आमजन को तहसील एवं पटवारी के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि वर्षों पूर्व आमजन और किसानों को अपने खाते की नकल पाना कठिन कार्य था, जिसे अब ऑनलाइन कर दिया गया है।

वाट्सएप पर भी किसान ले सकेंगे खसरा, बी-1 एवं ऋण-पुस्तिका

मध्य प्रदेश सरकार ने सरकार द्वारा किसानों या आमजन को उनके खाते की खसरा, बी-1 एवं ऋण-पुस्तिका की प्रति वाट्सएप पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। श्री राजपूत ने जनता से अपील करते हुए कहा कि राजस्व महकमे द्वारा सुविधाजनक रूप से किए गए बदलाव का ई-तकनीक के माध्यम से लाभ उठाएँ और परेशानी से बचें।

किसान मात्र 10 रुपए देकर ले सकेंगे ऋण पुस्तिका

किसानों और आम जनता को भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्त करने के लिए अब पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आम जनता की सुविधा के लिये भू-अधिकार ऋण पुस्तिका को ऑनलाइन कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी भू-अधिकार ऋण पुस्तिका को नजदीकी कियोस्क सेंटर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर या स्वयं के एन्ड्रायड मोबाइल से निर्धारित शुल्क 10 रूपये अदा कर ले सकता है।

कौन कौन से दस्तावेज ले सकते हैं ऑनलाइन

राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब मध्यप्रदेश के किसी भी जिले से संबंधित भूमि रिकॉर्ड को जनता ऑनलाइन घर बैठे देख सकती है। अब जन-मानस को सरकारी कार्यालयों में छोटी-छोटी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए बार-बार कार्यालय जाने की जरुरत नहीं है। मध्यप्रदेश भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से खसरा-खतौनी की नकल, भू-अभिलेख का रिकॉर्ड, आबादी सर्वे का रिकॉर्ड, बंधक भूमि की स्थिति, बंदोबस्त अधिकार अभिलेख, बंदोबस्त निस्तार पत्रक की स्केन प्रति, जमा बंधी नकल, खेत का नक्शा, विवादित भूमि का विवरण आदि ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

गौपालन एवं गौ संवर्धन बोर्ड को दान देने पर आयकर में छूट

भोपाल। आयकर विभाग द्वारा मध्यप्रदेश गौपालन एवं गौ संवर्धन बोर्ड को 80-जी (5)(ङ्क१) आयकर नियम 1961 के अंतर्गत छूट प्राप्त है। बोर्ड को www.gopalanboard.mp.gov.in पर ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से दान दिया जा सकता है। बोर्ड का बैंक खाता क्रमांक 10078152744 भारतीय स्टेट बैंक आईएफएससी कोड 0030388 शाखा नर्मदा भवन भोपाल है। दान की राशि आरटीजीएस/एनईएफटी करने पर दानदाताओं के नाम, पिता का नाम, वर्तमान का पता, पेन नंबर और आरटीजीएस/एनईएफटी का रेफरेंस नंबर और दिनांक बोर्ड को mpgopalanboard@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से भेजना होगी।दानदाताओं से अपील है कि गौशालाओं में आश्रित गौवंश के पालन एवं संवर्धन में सहयोग प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक दान करें एवं आयकर में प्राप्त छूट का लाभ उठाएं।

कृषि अवसंरचना कोष से मजबूत होगा खेती का बुनियादी ढांचा

डॉ. सत्येन्द्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित आत्मानिर्भर भारत अभियान पैकेज में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत एक लाख करोड़ का फंड प्रदान किया गया है। इसके तहत किसानों और अन्य कृषि संस्थानों को दो करोड़ तक का कर्ज दिया जाएगा, जिसमें सरकार ब्याज दर पर सब्सिडी देगी। योजना को शुरू हुये लगभग दो बर्ष होने को जा रहे हैं, लेकिन इस योजना की प्रगति बहुत धीमी बताई जा रही है। योजना के तहत पात्र किसान एवं अन्य संस्थाएं इस में कम रूचि दिखा रहे हैं।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हर मंच से योजना की खूबियों को गिनाकर लोगों से इसके तहत अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 'कृषि अवसंरचना कोष' की स्थापना की घोषणा की गई है। यह फंड फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश के लिये मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिये सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों से समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। 'कृषि अवसंरचना कोष' के तहत एक लाख करोड़ रुपए की वित्तपोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिये अगले चार वर्षों के दौरान एक लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 (10 वर्ष) तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स आदि हैं।

पूर्व में कृषि क्षेत्र के लिये सरकार द्वारा शुरू की गई अधिकांश योजनाएं कृषि उपज को बढ़ाने पर केंद्रित रही हैं। 1980 के दशक में कृषि क्षेत्र में वार्षिक निवेश देश की जीडीपी का लगभग 11प्रतिशत था जबकि वर्तमान में यह घटकर लगभग 7 प्रतिशत से भी कम हो गया है। इस योजना का उद्देश्य फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना। उपज बढ़ाने के लिये सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों हेतु धन उपलब्ध करना। लिये गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारिक तंत्र को मज़बूत करना है, जिससे देश के बड़े बाज़ारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनेटिक मानडंडों को पूरा करते हुए अंतराज्ट्रीय बाज़ारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। इस योजना के तहत 'टॉप अप' प्रणाली के तहत दोहरे लाभ की सुविधा प्राप्त हो सके, अथाज़्त यदि किसी पात्र

व्यक्ति को पहले से ही किसी अन्य योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त हो रही हो तब भी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा। इस योजना के तहत 2 करोड़ तक के ऋण पर 'क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़' के द्वारा गारंटी प्रदान की जाएगी साथ ही इस गारंटी के लिये ट्रस्ट का शुल्क केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके तहत ऋण (अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक) स्वीकृत होने से अगले 7 वर्षों तक सब्सिडी प्राप्त होती रहेगी। इस योजना के तहत ऋण के पुनर्भुगतान पर अधिस्थगन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष के बीच हो सकता है। 'कृषि अवसंरचना कोष' का प्रबंधन और निगरानी 'प्रबंधन सूचना प्रणाली' के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। इस प्रणाली के माध्यम से सभी पात्र संस्थान 'कृषि अवसंरचना कोष' से ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकेंगे। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान एवं क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज़, अनुमोदन की तीव्र प्रक्रिया के साथ-साथ अन्य योजना के लाभ के साथ एकीकरण जैसी सुविधा भी प्रदान करेगा। इस योजना की निगरानी और प्रभावी प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन और प्रोत्साहन का कार्य राज्यों द्वारा किया जाएगा। इसके लिये राज्य स्तर पर एक निगरानी समिति का गठन किया गया है, राज्य के मुख्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

कलेक्टर, ज़िला स्तरीय निगरानी समिति के अध्यक्ष होंगे और संबंधित ज़िले से नाबार्ड के ज़िला प्रबंधक तथा इस योजना में शामिल बैंकों के प्रधान प्रबंधक इस समिति के सदस्य होंगे। ज़िला स्तर पर संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा कृषि क्लस्टरों की पहचान और उनकी कमियों को रेखांकित करने का कायज़ संपन्न किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन को आसान बनाने के लिये एग्री इंफ्रा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्ति/संस्थान इस पोर्टल के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकेंगे। सरकार द्वारा इस योजना में शामिल बैंकों के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए है, जिससे बैंक अपनी इच्छा के अनुरूप दरों में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत ऋण वितरण के लिये 'सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर' से 1त्न से ऊपर की सीमा निधाज़रित की गई है। बैंक दिये गए ऋण पर ब्याज की दर में 1त्न से अधिक की बृद्धि नहीं कर सकेंगे। योजना के तहत सरकार द्वारा कृषि क्लस्टर की पहचान कर वहां उगाए जाने वाली फसलों के लिये आवश्यक अवसंरचना के विकास और इसके लिये आवश्यक सहयोग प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

फलोत्पादन से पाएं पोषण सुरक्षा, बीमारियों से बचें

डॉ. शालिनी चक्रवर्ती
वरिष्ठ वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान
कृषि विज्ञान केन्द्र, राजगढ़ (म.प्र.)
राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

हमारे भोजन में फलों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनसे हमें विटामिन एवं खनिज लवणों के अतिरिक्ति प्रोटीन, वसा तथा श्वेतसार भी प्राप्त होता है। फलों का संतुलित प्रयोग करके हम पोषक तत्वों की कमी द्वारा होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 110 ग्रा. फल खाने की सलाह दी गयी हैं। किन्तु हमारे देष में प्रति व्यक्ति 60 ग्रा. फल ही उपलब्ध हो पाता है जो आवश्यकता से काफी कम है एवं इसका सेवन भी फल के मौसम तक ही सीमित होता है।

बाजार में फलों का बढ़ता मूल्य भी लोगों को फल सेवन से दूर करने में सहायक है। जब लोग कम मात्रा में अथवा असंतुलित रूप में फलों का उपयोग करते हैं, उन्हें विटामिन एवं खनिज लवणों की कमी के द्वारा होने वाली बीमारियां हो जाती हैं। निम्न आय वर्ग के लोगों में कुपोषण के कारण जन्म के समय नवजात शिषु का वजन कम होता है एवं उसकी मुत्यु दर अधिक होती है। लोहे की कमी के कारण खून की कमी हो जाती हैं। बालकों में विटामिन 'ए' की कमी के कारण अंधापन हो जाता हैं। हमारे समाज के लगभग आठ प्रतिषत बच्चों के अंधेपन का यही कारण हैं। विटामिन बी समूह की कमी भी मुख्यत: निम्न आय वर्ग के लोगो में अधिक होती हैं। उपरोक्त कारणों से हमारा मानव संसाधन विशेषकर श्रम शक्ति बड़े पैमाने पर प्रभावित होती हैं एवं उससे हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता प्रभावित होती है। अत: यह बहुत आवश्यक है कि लोगो को फलों की महत्ता एवं उनके पौष्टिक गुणों की जानकारी दी जाए। ताजे फलों में फास्फोरस, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेषियम आदि की मात्रा उपल्बध होती है, जिससे स्वस्थ्य शरीर संतुलित अवस्था में रहता है और शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। सारणी एक तथा दो में ताजे फलों में उपलब्ध मुख्य खनिज तत्व तथा विटामिनों के बारे में जानकारी दी गई हैं।

खनिज तत्व के स्रोत और उनका महत्व

फास्फोरस: यह कैल्शियम के साथ हड्डियों, दांतों तथा मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। काबोहाईड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। यह केला, रसभरी, कैथा, अनार, पैशन फल, एवोकैडो आदि में पाया जाता है।

लोहा: यह शरीर के लाल रूधिर कणिकाओं में पाये जाने वाले हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव है। यह शरीर में कार्यरत अनेक एन्जाइमों में उपस्थित रहता है। इसकी कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती हैं, जिससे मनुष्य रोगी तथा कमजोर हो जाता है। यह अमरूद, केला, कच्चा आम, शहतूत, सेब, फालसा, अनन्नास, आवंला, बेर, नींबू, लोकाट, पैशन फल आदि में पाया जाता है।

सोडियम: यह शरीर के ऊतकों तथा तंत्रिका तंत्र के विकास में सहायक होता है। इसकी कमी से रक्तचाप पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह सेब, केला, लीची, जामुन, पपीता, अनन्नास, अनार, अमरूद, फालसा, नाशपाती आदि में पाया जाता है।

मैग्नीशियम: कैल्शियम एवं फास्फोरस के पाचन के अलावा कई एन्जाईमों की क्रियाओं में इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियों के उचित संचालन में भी इसका विशिष्ट स्थान है। इससे मधुमेह एवं आंतों की बीमारी हो जाती है। यह आलू बुखारा, केला, अंगूर आदि में पाया जाता है।

सल्फर: यह मांसपेशियों एवं हड्डियों के विकास के लिए आवष्यक अमीनो एसिड एवं प्रोटिन बनाता है तथा जहरीले पदार्थों के दुष्प्रभाव को खत्म करता है। यह कटहल, रसभरी, तरबूज आदि में पाया जाता है।

कॉपर: यह लोहे के अवषोषण एवं लोहे से संबंधित क्रियाओं में भाग लेता है। कई इन्जाईमों की क्रियाओ में इसकी उपस्थिति आवश्यक है। यह सेब, अनार, पपीता, रसभरी, नाषपाती, शरीफा, संतरा, नीबूं, केला आदि में पाया जाता है।

क्लोरीन: यह शरीर में अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाता है तथा तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। यह खुबानी, अनन्नास, स्ट्रॉबेरी आदि में पाया जाता है।

कैल्शियम: हमारे शरीर में दांत एवं हड्डियों का अधिकांश भाग कैल्शियम से बना होता है। कैल्शियम हड्डियों एवं शरीर के द्रवों में पाया जाता है। इसकी अल्पता से बच्चों में सूखा रोग एवं बड़ों में ओस्टोमेलेशिया हो जाता है। यह पपीता, नींबू, माल्टा, आवंला , अमरूद, कैथा, स्ट्रॉबेरी, बेल, बेर आदि में पाया जाता है।

पोटेशियम: यह प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। यह क्षरीयता एवं अम्लता का संतुलन बनाऐ रखने में भी सहायता करता है। इसकी कमी से फेफड़ों की बीमारी हो जाती हैं। यह कटहल, केला, खुबानी, अंगूर, अमरूद आदि में पाया जाता है।

दुनिया में 80 फीसदी से अधिक कृषि भूमि को होगी पानी की कमी

जलवायु में हो रहे बदलावों के कारण पानी की उपलब्धता पर इसके बुरे प्रभाव पड़े हैं, परिणामस्वरूप दुनिया के कई क्षेत्रों में फसल उत्पादन में समस्या उत्पन्न हुई है। पिछले 100 वर्षों में दुनिया भर में पानी की मांग लोगों की आबादी की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ी है। कृषि के साथ हर महाद्वीप पर पानी की कमी पहले से ही एक गंभीर मुद्दा है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। अब एक नए अध्ययन में कहा गया है कि 2050 तक दुनिया के 80 फीसदी से अधिक खेती की जाने वाले इलाकों में पानी की भारी कमी होने के आसार हैं। यह नया अध्ययन वैश्विक कृषि के लिए वर्तान और भविष्य के पानी की आवश्यकताओं के बारे में पता लगता है। अध्ययन में यह भी अनुमान लगाया गया है कि बारिश से सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी का स्तर जलवायु परिवर्तन के तहत उन जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं। ऐसा करने के लिए शोधकर्ताओं ने कृषि के दो प्रमुख स्रोतों में पानी की कमी को मापने और अनुमान लगाने के लिए एक नया सूचकांक बनाया है। मिट्टी में पानी जो बारिश से आता है, जिसे ग्रीन या हरा पानी कहा जाता है, नदियों, झीलों और भूजल से सिंचाई में उपयोग होने वाले को नीला पानी कहा जाता है।

दुनिया भर में इस व्यापक सूचकांक को लागू करने और जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप दुनिया भर में नीले और हरे पानी की कमी के बारे में जांच पड़ताल करने वाला यह पहला अध्ययन है। प्रमुख अध्ययनकर्ता जिंगकाई लियू ने कहा कि नीले और हरे दोनों जल संसाधनों के सबसे बड़े उपयोगकर्ता के रूप में, कृषि उत्पादन को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लियू, चीनी विज्ञान अकादमी के भौगोलिक विज्ञान और प्राकृतिक संसाधन अनुसंधान संस्थान के एक सहयोगी प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा यह सूचकांक एक सुसंगत तरीके से वर्षा आधारित और सिंचित दोनों फसलों में कृषि जल की कमी का आकलन करने में सक्षम है। पानी की कमी पहले से ही एक गंभीर मुद्दा है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पेश कर रहा है। इसके बावजूद, अधिकांश पानी की कमी वाले मॉडल नीले और हरे दोनों तरह के पानी पर व्यापक नजर डालने में अभी तक विफल रहे हैं।

हरा पानी या ग्रीन वाटर वर्षा जल का वह भाग है जो मिट्टी में पौधों के लिए उपलब्ध होता है। अधिकांश वर्षा हरे पानी के रूप में मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि यह मिट्टी में दिखता नहीं है। फसलों के लिए उपलब्ध हरे पानी की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है और पानी के बहने और वाष्पीकरण के कारण कितना पानी नष्ट होता है।

अलबामा विश्वविद्यालय में सिविल, निर्माण और पर्यावरण इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर मेसफिन मेकोनेन ने कहा कि खेती की जाने वाले इलाकों में पानी की उपलब्धता किस समय में कितनी होगी इस पर जलवायु का असर भी पड़ेगा। शोधकर्ताओं ने पाया कि जलवायु परिवर्तन के चलते वैश्विक कृषि में पानी की कमी 84 फीसदी तक खेती की भूमि को बर्बाद कर सकती है, पानी की आपूर्ति में कमी के कारण लगभग 60 फीसदी खेती की भूमि में कमी हो जाएगी।

नया सूचकांक देशों को कृषि जल की कमी के खतरे और कारणों का आकलन करने और भविष्य के सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद कर सकता है। कई प्रथाएं कृषि जल के संरक्षण में मदद करती हैं। मल्चिंग या मिट्टी को घास-पात से ढकने से वाष्पीकरण को कम किया जा सकता है। खेती में उपयोग होने वाले पानी को सही समय के अनुसार दिया जाना चाहिए। लियू ने कहा भविष्य को देखते हुए सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाना चाहिए। यह अध्ययन एजीयू जर्नल अर्थ्स फ्यूचर में प्रकाशित हुआ है।

बेटियों को प्रेम, स्नेह और सम्मान देने का भागीरथी प्रयास है, मध्यप्रदेश के मामा शिवराज की लाड़ली लक्ष्मी योजना-कमल पटेल

अब लाड़ली लक्ष्मी 2.0 की शुरुआत से और भी बेहतर होगा प्रदेश की बेटियों का भविष्य

भोपाल, जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वषज़ 2007 में प्रदेश की बेटियों का भविष्य बेहतर करने और समाज में उनकी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का एक स्वप्न देखा और एक ऐसा अडिग संकल्प लिया जिसने उनके संवेदनशील ह्रदय और इसमें बसने वाली जन-कल्याण की पवित्र और अदम्य भावना का परिचय पूरे प्रदेश के साथ-साथ देश को भी कराया 7 लाड़ली लक्ष्मी योजना ने अनगिनत बच्चियों के जीवन को आलोकित करने का कायज़ किया और उनके साथ ही उनके अभिभावकों के जीवन में भी सुखद बदलाव ला दिये7 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की दूर दृष्टि और सोच का ही परिणाम है कि आज प्रदेश की कई बेटियाँ मुस्कुराते और दमकते चेहरों के साथ बेहतर भविष्य के सपने संजो रही हैं 7

बेटियों के प्रति समाज की नकारात्मक सोच, लड़कों के मुकाबले उनकी कम होती संख्या, बालिका शिक्षा की कमजोर स्थिति बेटियों को जल्दी ब्याहना जैसी समस्याओं से निपटने के लिए और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाइली लक्ष्मी योजना 01 अप्रैल 2007 में शुरू की गई। बीते 15 सालों में लाड़ली लक्ष्मी योजना को न सिफज़ मध्यप्रदेश बल्कि अन्य राज्यों ने भी प्रभावी ढंग से अपनाया और इसके सुखद परिणाम हासिल किये । इस कल्याणकारी योजना में वषज़ 2007 से अब तक 42.00 लाख से अधिक बालिकाओं का पंजीयन किया गया है यानि लगभग 84.16 लाख माता-पिता इससे लाभान्वित हुए हैं ।

लाडली लक्ष्मी योजना की इस अभूतपूवज़ सफलता को देखते हुए बालिकाओं को आज के समय के अनुसार सशक्त और आत्मनिभज़र बनाने एवं आथिज़क रूप से सशक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना को और भी अधिक बेहतर बनाते हुए लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 तैयार की है। जिसमें कई नए प्रयास और नवाचार करते हुए बालिकाओं को उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है, जो उनके भविष्य के मागज़ को और अधिक बेहतर बनाने का कायज़ करेगी ।

इसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में कक्षा 06, कक्षा 09 कक्षा 11 एवं कक्षा 12 में प्रवेशित और अध्ययनरत कुल 9.05 लाख बालिकाओं को राशि 231.07 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण भी किया गया है । लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ 12वीं कक्षा के बाद ही मिलना सुनिश्चित किया गया ताकि बालिका की शिक्षा-दीक्षा भी ठीक ढंग से पूणज़ हो सके अत: इस योजना में यह नियम होने से बालिकाओं की शिक्षा की निरन्तरता भी सुनिश्चित हुई है। इस योजना का ही फल है की लाड़ली लक्ष्मी योजना के कारण बालिकाओं की शिक्षा में भी सुधार हुआ है। आज लगभग 93 प्रतिशत लोग बेटी को 12 वीं से अधिक पढ़ाना चाहते हैं और परिणामस्वरूप लड़कियों की स्कूल में फिर से दाखिला लेने की संख्या और उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संख्या में काफी सुधार आया है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना का एक और सुखद परिणाम यह भी रहा कि प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में भी काफी कमी आई क्योंकि इस योजना का लाभ कन्या के 18 वषज़ के बाद विवाह होने पर ही मिलता है । वर्ष 2011 की जनगणना के समय प्रदेश का शिशु लिंगानुपात केवल 919 था। NFHSS के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर अब 956 हो चुका है। विशेषकर ग्वालियर चंबल और बुंदेलखंड जैसे कम लिंगानुपात वाले क्षेत्रों में लिंगानुपात में सकारात्मक परिवतज़न आया है। इन इलाकों में केवल बेटे के जन्म के समय शहनाई बजती थी, पर अब बेटियों के जन्म का उत्सव भी मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के पावन संकल्प लाड़ली लक्ष्मी योजना के कारण ही यह संभव हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मागज़दशज़न में आगे बढ़ते हुए हरदा क्षेत्र में भी इस योजना में बहुत अच्छा काम हुआ है वषज़ 2007 से आज तक कुल 31455 बालिकाओं को लाभांवित किया गया है जिसमें विकासखण्ड हरदा में 12181, टिमरनी विकासखण्ड में 9631 एवं खिरकिया विकासखण्ड में 9536 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है 7 लाड़ली बालिकाओं की लाड़ली निधि में 6000 रूपये प्रति किश्त के मान से 30000 रूपये की राशि जमा करते हैं तथा लाडली बालिकाओं की छात्रावृत्ति की राशि कक्षा 6वीं में 2000 रूपये, 9वीं में 4000रूपये, 11वी में 6000 रूपये एवं 12वीं में 6000 रूपये की राशि दी जाती है साथ ही लाडली के 18 वर्ष के बाद विवाह होने तथा 12वी में प्रवेश होने पर एवं 21 वषज़ की उम्र में 1 लाख रूपये की राशि बालिका को दी जाती है।मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सभी पूरे प्रदेश में एक साथ लाडली लक्ष्मी उत्सव को मना रहे है। प्रदेश भर की इस महत्वाकांक्षी योजना, जिसकी पूरे देश में प्रशंसा हुई है, निश्चित ही प्रदेश की लाडली बालिकाओं का भविष्य उज्जवल होगा। मै समस्त लाड़ली बालिकाओं और उनके अभिभावको को हार्दिक बधाई देता हूँ।

- कृषि, पशुपालन, फॉरेस्ट, माईनिंग एवं पब्लिक वर्कस लाईन डिपार्टमेंट के तहत किए जाएंगे कार्य

चंबल किनारे के 96 गांवों का ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में चयन, होंगे पर्यावरण सुधार के काम

खेमराज मौर्य। शिवपुरी/श्योपुर

श्योपुर और मुरैना जिले के चंबल नदी किनारे बसे 96 गांवों में अब पर्यावरण सुधार संबंधी कार्य किए जाएंगे। वहीं कृषि, पशुपालन, फॉरेस्ट, माइनिंग एवं पब्लिक वर्कस लाइन संबंधी कई कार्य भी कराए जाएंगे। दरअसल यह गांव चंबल नेशनल सेंचुरी के अन्तर्गत आते है,इसलिए इन गांवों का चयन ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत किया गया है।

बीते सप्ताह श्योपुर में आयोजित हुई ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलीटी की बैठक में फूड एण्ड एग्रीकल्चर ऑर्गनाईजेशन के सीनियर पॉलिसी एडवाईजर राकेश सिन्हा ने ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, भूमिक्षरण, ओजोन परत कार्बनिक प्रदुषण प्रबंधन, टिकाऊ वन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण स्थिरता विकास को बढावा देना है। जिससे वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा में सहायता मिल सकें। उन्होने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत 05 राज्यों में कार्य किया जायेगा। मप्र में श्योपुर-मुरैना चंबल नेशनल सेंचुरी क्षेत्र को चयनित किया गया है। जिसके तहत 96 ग्रामों में पर्यावरण संबंधी कार्य होगे। इस प्रोजेक्ट के तहत उक्त ग्रामों की 96 हजार 143.2 हेक्टयर भूमि को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट के तहत कृषि, पशुपालन, फॉरेस्ट, माईनिंग एवं पब्लिक वर्कस लाईन डिपाटमेंट के तहत कार्य किये जायेंगे। उन्होने कहा कि सभी संबंधित विभाग मिलकर कम्युनिटी के साथ बैठकर प्लांनिग करें तथा विलेज डबलपमेंट प्लान बनायें। बैठक में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गनाईजेशन के असिस्टेंट एवं रि-प्रजेंटेटिव इंडिया कोण्डा रेड्डी द्वारा प्रोजेक्ट के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

सपोर्ट के लिए गठित होंगी समितियां

इस प्रोजेक्ट के सपोर्ट के लिए नेशनल, स्टेट लेवल के साथ ही जिला एवं पंचायत स्तर पर कमेटिया गठित की जायेगी। ताकि इस प्रोजेक्ट को संचालित होने में किसी तरह की कोई बाधा न आए और इस प्रोजेक्ट के चयनित गांवों के ग्रामीण भी इस संबंध में जागरूक होकर सहयोगी बने। सीनियर पॉलिसी एडवाईजर राकेश सिन्हा ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत संवहनीय कृषि, पशुपालन प्रबंधन, कम्युनिटी बेस्ड इकोटूरिज्म, मेडिशनल एवं एरोमेटिकल प्लांटेशन आदि के क्षेत्र में कार्य किया जायेगा। पर्यावरणनीय अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु सभी पैरामीटर्स पर कार्य किया जायेगा।

संबंधित विभाग समय सीमा में पूर्ण करें कार्य

इस बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा भी उपस्थित थे, कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिये कि अपने-अपने विभाग से संबंधित कार्य समय सीमा में पूर्ण किये जायें तथा बेसलाइन सर्वे का कार्य पूरा किया जायें। इसके साथ ही प्रोजेक्ट के तहत तीन दिन की कार्यशाला आयोजित कर प्रारंभिक तैयारियों का डाक्यूमेंशन किया जाए। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ राजेश शुक्ल, डीएफओ कूनो पीके वर्मा सहित जल संसाधन, पशु चिकित्सा विभाग, कृषि, जनजातीय कार्य विभाग, चंबल अभ्यारण, उद्यानिकी, मत्स्य, वाटरशैड, एनआरएलएम आदि विभागों के उपस्थित थे।

बांस के मामले में समृद्ध हुआ मध्य प्रदेश, कई जिलों को मिलेगा लाभ

भोपाल। मध्यप्रदेश में वन क्षेत्र को समृद्ध करने की तैयारी पूरी की जा रही है। दरअसल बांस के मामले में प्रदेश को बेहद समृद्ध बनाया गया है। वहीं ट्री कवरके मामले में प्रदेश पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर है। साथ ही इन नवीन उपलब्धि हासिल करते हुए मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। इस साल 2022 के अंत तक 5000 वन समितियों के माइक्रो प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया है। मामले में वन मंत्री विजय शाह ने बड़ी घोषणा की है।

वन समितियाँ विशेष भूमिका निभा रही- वन मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह ने कहा कि प्रदेश के वनों के सुधार और प्रबंधन में वन समितियाँ विशेष भूमिका निभा रही हैं। इस वर्ष के अंत तक 5 हजार वन समितियों के माइक्रो प्लान तैयार कर लिये जायेंगे। वन मंत्री डॉ.विजय शाह ने बताया कि प्रदेश में 847 ग्राम समुदाय ऐसे हैं, जहाँ वनों में सुधार किया गया है। इसके अलावा 390 ग्रामों में 1.15 लाख हेक्टेयर बिगड़े वन क्षेत्र का पूर्ण रूप से सुधार किया जा चुका है। पिछले एक दशक में प्रदेश के 1152 ग्रामों में 4 लाख 31 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र में सुधार किया गया।

बांस के मामले में प्रदेश हुआ समृद्ध

बांस के मामले में प्रदेश समृद्ध हुआ है। यहाँ 18 हजार 394 वर्ग किलोमीटर में बांस उपलब्ध है, जो देश में सर्वाधिक है। इसमें हरे डंठल का बांस 3108 मिलियन और सूखे डंठल वाला बांस 1005 मिलियन है।

ट्री कवर में प्रदेश तीसरे स्थान पर

प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 3 लाख 8 हजार 292 वगज़ किलोमीटर है। इसमें से ट्री कवर 8054 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.61 फीसदी है। इस तरह ट्री कवर की दृष्टि से देश के प्रथम पाँच राज्यों में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर काबिज है। भारतीय वन सर्वेक्षण की 2021 की जारी रिपोटज़ के अनुसार वन क्षेत्र में प्रदेश अन्य राज्यों से आगे है। अति सघन वन क्षेत्र 6645 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वन 34 हजार 209 वर्ग किलोमीटर और खुला वन क्षेत्र 36 हजार 619 वगज़ किलोमीटर है।

सतावर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान

किसानों को कम समय में मालमाल कर सकती है सतावर की खेती

भोपाल। सतावर की खेती औषधीय फसल के रूप में की जाती है। यह एक ऐसा पौधा है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से औषधीय दवाइयों को बनाने में किया जाता है। सतावर की खेती भारत के अलावा चीन, नेपाल, अफ्रीका, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलियाव अन्य देशो में भी की जाती है, वही भारत में राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में इसकी खेती को मुख्य रूप से किया जाता है। सतावर की जड़े भूमि के अंदर लगभग 6 से 9 इंच गहराई में पाई जाती है। इसलिए इसकी खेती में रेतीली भूमि की आवश्यकता होती है। रेतीली भूमि में इसकी जड़ों को फैलने के लिए सुविधा प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त इसे हल्की कपासिया तथा चिकनी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। सतावर की खेती को अच्छी जल निकासी वाली भूमि में ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। इसके पौधों के अच्छे विकास के लिए गर्म अवं आद्र जलवायु की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों का तापमान 10 डिग्री तापमान से 50 डिग्री तापमान के मध्य होता है, वह क्षेत्र इसकी उपज के लिए काफी अच्छा होता है। ठन्डे क्षेत्रों के अलावा इसकी खेती को पूरे भारत में कही भी किया जा सकता है।

सतावर के खेत की तैयारी

सतावर के पौधे को तैयार होने में 18 से 24 माह का समय लग जाता है। इसलिए इसके खेत को प्रारम्भ से ही अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत को मई-जून के माह में गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दे, फ़ि उसमे प्राकृतिक खाद के रूप में 2 टन पुरानी सड़ी गोबर की खाद को डाल दे। इसके अलावा रासायनिक खाद के रूप में 120 च्त्र प्रॉम जैविक खाद की मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। खाद को खेत में डालने के बाद जुताई कर खाद को अच्छे से मिला दे। इसके बाद खेत में 60 ष्टरू की दूरी रखते हुए 9 इंच की मेड़ को तैयार कर ले।

उन्नत किस्में

एस्पेरेगस एडसेंडेस, एस्पेरेगस सारमेन्टोसस, एस्पेरेगस स्प्रेन्गेरी, एस्पेरेगस आफीसीनेलिस, एस्पेरेगस फिलिसिनस, एस्पेरेगस कुरिलस, एस्पेरेगस गोनोक्लैडो, एस्पेरेगस प्लुमोसस आदि। इसमें एस्पेरेगस एडसेन्डेस को सफद मूसली के रूप में जाना जाता है, तथा एस्पेरेगस सारमेन्टोसस को महाशतावरी कहा जाता है, जो हिमालय क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसकी एक किस्म एस्पेरेगस आफीसीनेलिस है, जिसे सूप तथा सलाद बनाने के लिए उपयोग में लाते है।

रोपाई का तरीका

सतावर के बीजो की रोपाई को बीज के रूप में किया जाता है। बीजों की रोपाई को कंद के रूप में किया जाता है, जिनसे पौधे तैयार होते हैं। इससे प्राप्त हुए अंकुरों को पौधों से अलग कर पॉलीथीन बैग में रख दिया जाता है। इसके बाद इन अंकुरों को 25 से 30 दिन में पॉलीथीन से बाहर निकाल कर खेत में स्थानांतरित कर दें। बीजों की रोपाई के लिए बीजों को तैयार करने के लिए नर्सरी को तैयार करना जरूरी होता है।

कैसे तैयार करें नर्सरी

सतावर की खेती को व्यापारिक रूप से करने के लिए इसके बीजों को नर्सरी में तैयार करना होता है। एक एकड़ के खेत में सतावर की फसल करने के लिए तक़रीबन 100 वर्ग फीट में नर्सरी को तैयार करना होता है। इसके लिए भूमि में खाद डालकर अच्छे से तैयार कर ले। नर्सरी में पौधों की ऊंचाई पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे इन्हे आसानी से उखाड़ कर स्थानांतरित किया जा सके। एक एकड़ के खेत में लगभग 2 किलो बीज की आवश्यकता होती है, इसके बीजों को मध्य माह में लगाया जाता है। बीजों की रोपाई के बाद उसके ऊपर गोबर मिश्रित मिट्टी को चढ़ा देना चाहिए। इससे बीज अच्छी तरह से ढक जायेंगे। इसके बाद स्प्रिंकलर्स विधि द्वारा बीजों की हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इनके बीजो का अंकुरण 10 से 15 दिनों में आरम्भ हो जाता है, तथा 40 से 45 दिनों बाद इसके पौधों को पॉलीथीन की थैलियों में रखकर भी तैयार कर सकते हैं।

पौधों की सिंचाई

सतावर के पौधों को अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, किन्तु इसके पौधों की एक महीने में सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। सिंचाई के लिए फ्लड पद्धति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में सिंचाई होने से पौधों की जड़ो का अच्छे से विकास होता है। जल-भराव न ही इसका ध्यान रखना जरूरी है।

लगने वाले रोग

सतावर के पौधों में बहुत ही कम रोग देखने को मिलते हैं, साथ ही इसके पौधों को जानवरों के खा जाने का खतरा भी कम होता है, क्योंकि इसके पौधों का ऊपरी हिस्सा कांटेदार होता है।

खरपतवार नियंत्रण

सतावर के पौधों में प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। इसके पौधों को जरूरत पड़ने पर ही खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। इससे खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई ङ्क गुड़ाई करने से भूमि की मिट्टी भी नर्म बनी रहती है, और पौधों की जड़ो के लिए उपयुक्त वातावरण भी मिल जाता है।

जड़ों की खुदाई

सतावर की फसल को तैयार होने में 18 से 30 माह का समय लग जाता है। इतना समय हो जाने पर इसके पौधों की खुदाई कर लेनी चाहिए। इसके जड़ों की खुदाई के लिए अप्रैल-मई के माह को उचित माना जाता है।

अजवाइन की खेती कैसे होती है

अजवाइन एक झाड़ीनुमा वनस्पति है, जिसे मसाले एवं औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसकी खेती को छोटे पैमाने पर किया जाता है। यह देखने में धनिया कुल प्रजाति का पौधा होता है, इसकी लम्बाई लगभग एक मीटर तक होती है। अजवाईन के दानों में कई तरह के खनिज तत्वों का मिश्रण उपस्थित होता है, जो मानव शरीर के लिए काफी लाभदायक होता है। अजवाईन की खेती को करने का एक ही समय रबी की फसल का होता है।

अजवाईन की खेती में अधिक बारिश की आवश्यकता नहीं होती है तथा सर्दिय्यों का मौसम इसके पौधों को विकास करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसके पौधे सर्दियों में गिरने वाले पाले को भी सहन कर लेते हैं। अजवाईन का बाजारी भाव काफी अच्छा होता है। इसलिए किसान अजवाईन की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसकी खेती की लिए जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप अधिक पैदावार प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बलुई मिट्टी में इसकी खेती को करना चाहिए। अधिक नमी तथा जलभराव वाली जगहों पर इसकी खेती को नहीं किया जा सकता है। अजवाईन की खेती में भूमि का पीएच मान 6.5 से 8 के मध्य होना चाहिए। इसके पौधों को अच्छे से विकास करने के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। किन्तु फूलों के बीजों को पकने के दौरान इसे गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, तथा इसके लिए बिलकुल खुली धूप होनी चाहिए। अजवाईन के पौधों को आरम्भ में विकसित होने के लिए 20 से 25 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। सर्दियों के मौसम में यह पौधे न्यूनतम 10 डिग्री तापमान पर अच्छे से विकास करते हैं। पौधों में लगे दानों को पकने के लिए 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है।

अजवाईन की किस्में

वर्तमान समय में अजवाईन की पैदावार को बढ़ाने के लिए बाजार में कई तरह की किस्मे मौजूद है। जिन्हे अलग-अलग जलवायु के हिसाब से अलग-अलग स्थानों पर उगाया जाता है। यह सभी पककर तैयार होने के उत्पादन के आधार पर की जाती है।

लाभ सलेक्शन 1

यह किस्म कम समय में अच्छी पैदावारदेती है। इस किस्म को राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में उगाया जाता है। इसमें पौधों के दाने बीज रोपाई के लगभग 130 से 140 दिन पककर तैयार हो जाते है। इसमें पौधा एक मीटर तक लम्बा होता है। इसका प्रति हेक्टयेर उत्पादन 8 से 9 क्विंटल के मध्य होता है।

लाभ सलेक्शन 2

पौधों की यह किस्म सिंचित और असिंचित दोनों ही भूमि में अधिक उत्पादन देने के लिए उगाई जाती है। इसमें पौधे लगभग 135 दिन में पककर तैयार हो जाते है। इसमें प्रति हेक्टयेर उत्पादन 10 क्विंटल तक होता है। इसके अतिरिक्त भी अजवाईन की कई किस्में पायी जाती है जिनमे ऐ ऐ 2,आर ए 1-80,गुजरात अजवाइन 1,आर ए 19-80 जैसी किस्मे मौजूद है।

खेत और पौधों की तैयारी

अजवाइन की खेती में भुरभुरी और साफ मिट्टी की आवश्यकता होती है। खेत में मौजूद पुरानी फसलों के अवशेषों को नष्ट करने के लिए खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर दें जिससे सभी पुराने अवशेष निकल जायेंगे। इसके बाद खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर खेत को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जुताई के बाद खेत में पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। खेत की मिट्टी भुरभुरी होने के बाद पाटा लगा कर चला दे जिससे खेत बिलकुल समतल हो जायेगा।

जीरे की खेती, फायदे का सौदा

भोपाल। आजकल परंपरागत खेती छोड़कर लोग नकदी फसलों की खेती में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। ऐसे कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाली मशाला फसल जीरा एक लाभदायक फसल तो है ही साथ ये एक मुल्यावर्धक फसल भी है। इसकी खेती का लाभ लेकर आप भी साल की अच्छी आमदनी कर सकते हैं। जीरे की खेती के लिये हल्की एवं टोमट उपजाऊ मिट्टी अधिक अच्छी मानी जाती है, जिससे जीरे की खेती आसानी से की जा सकती है। **प्रमुख किस्में**

आर एस 1-यह एक जल्दी पकने वाली किस्म है। इसका बीज कुछ बड़ा रोयेदार होता है। यह देशी किस्म की अपेक्षा अधिक रोग रोधी तथा 20-25 प्रतिशत अधिक उपज देती है। यह किस्म 80-90 दिनों में पककर 6-10 क्वि. प्रति हैक्टेयर उपज देती है।

गुजरात जीरा 2- यह किस्म 100 दिन में पककर। क्वि. प्रति हैक्टेयर उपज देती है।

आर.जेड-209- इस किस्म के दोने सुडोल, बडे व गहरे भूरे रंग के होते है। यह फसल 120-125 दिन में पककर 6-7 क्वि. प्रति हैक्टेयर उपज देती है। इस किस्म में छाछ्या रोग का प्रकोप आ.जेड.-19 की तुलना में कम लगता है।

आर जेड 19 - इस किस्म के दोने सुडौल, आकर्षक तथा गहरे भूरे रंग के होते है। यह 125 दिन में पक जाती है एवं स्थानीय किस्मों तथा आर एस 1 की तुलना में उखटा, छाछ्या व झुलसा रोग से कम प्रभावित होती है। इस किस्म का उपज 10.5 क्वि. प्रति हैक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है।

खेत की तैयारी- खेती करने से पहले जरूरी है की खेत को फसल के अनुकूल तैयार किया जाना चाहिए। खेत की अच्छी तरह से जोत कर उसकी मिट्टी भुरभरी

खाद व उर्वरक

- सभी खरीफ की फसल में अगर 10-15 टन प्रति हे. गोबर की खाद डाली गई है हो तो जीरे की फसल के लिये अतिरिक्त खाद की आवश्यकता नहीं है यदि ऐसा नहीं किया गया हो तो 10-15 टन प्रति हे. के हिसाब से जुताई से पहले गोबर की खाद खेत में बिखरे कर भूमि में मिला देना चाहिए।
- जीरे की फसल में 28 कि.ग्रा. नत्रजन एवं 21 कि.ग्रा. फास्फोरस प्रति हे. की दर से उर्वरक भी दें। फास्फोरस की पूरी मात्रा बुवाई से पूर्व आखिरी जुताई के समय भूमि में मिला देना चाहिए एवं नत्रजन की आधी मात्रा बुवाई के 32 -35 दिन के बाद एवं शेष आधी 15 कि.ग्रा. नत्रजन बुवाई के 55 दिन बाद सिंचाई के साथ दें।

बुवाई की विधि

एक हे. क्षेत्र के लिये 12-16 किलो ग्रा. बीज पर्याप्त रहता है। बुवाई से पूर्व जीरे के बीज को 2 ग्रा. कार्बेन्डाजिम की बराबर मात्रा मिलाकर प्रति कि.ग्रा. बीज के हिसाब से उपचारित कर बोना चाहिए तथा जीरे की बीज की बुवाई 15 से 30 नवम्बर के बीज कर देनी चाहिए।

कब करें सिंचाई

बुवाई के तुंरत बाद एक हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई के समय ध्यान रहे की पानी का बहाव तेज न हो अन्यथा तेज बहाव से बीज अस्त व्यस्त हो जायेगे। दूसरी सिंचाई बुवाई एक सप्ताह पूरा होने पर जब बीज फूलने लगें तब करें। दाने बनते समय अन्तिम सिंचाई करे। परंतु पकती हुई फसल में सिंचाई न करें।

झुलसा रोग

फसल में रोग के लक्षण दिखाई देते ही नियंत्रण हेतु बुवाई 30-35 दिन बाद फसल पर 2 ग्रा. थियोफेनेट मिथाईन या मैकोंजेब को प्रति ली. पानी की घोलकर छिड़कें। झुलसा रोग नियंत्रण हेतु ट्राईकोडर्मा विरीडी जैविक फफूंदनाशक दवा की 4 ग्राम मात्रा प्रति किलो के बीज की दर से बीजोपचार करके बुवाई करे और बुवाई के 35 दिन पश्चात् प्रोपेकोनेजोल एक मि.ली. प्रति ली. पानी की घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।

पीएम किसान खाद योजना की राशि सीधे किसानों के खाते में-

किसानों को खाद खरीदने के लिए मिलेंगे 11 हजार रुपए, जानिए कैसे

भोपाल। भारत सरकार क्षरा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रहीं हैं। इसी क्रम में सरकार ने किसानों की भलाई के लिए वरीएम किसान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत देश के किसानों को सरकार के द्वारा उर्वरक उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना की स्थापना रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि सरकार अपनी इस योजना में देश के सभी किसानों को खाद खरीदने के लिए 11 हजार रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। जिससे देश के किसान खेती करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें और अपनी आय को दो गुना बढ़ा सके।

सरकार अपनी इस योजना के तहत किसान भाइयों को खाद खरीदने के लिए 11 हजार रुपए तक आर्थिक सब्सिडी दे रही है। खाद की इस राशि को किसानों के खातों में दो किस्तों में दिया जायेगा। पहली किस्त 6000 रूपए और वहीं दूसरी किस्त 5000 हजार रुपए है। यह दोनों किस्त ऑनलाइन तरीके से सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

योजना के लिए जरूरी कागजात

अगर आप भी सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको देश का किसान होना चाहिए और साथ ही नीचे दिए गए जरूरी कागजात भी आपके पास होने चाहिए।

- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- किसान की पासपोर्ट साइज फोटो

ऐसे करें आवेदन

- योजना का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान खाद्य योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
- इसके बाद आपको साइट के डीबीटी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जहां आपको पीएम किसान के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से आपको समक्ष पीएम किसान खाद्य योजना का ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा।
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही व विस्तार से भरना होगा।
- इसके बाद आपको अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर को इसमें दर्ज करना होगा और फिर दिए गए कैप्चा कोड को भरकर सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह से आप इस योजना की आवेदन प्रक्रिया को सरलता से पूरा कर सकते हैं।

बकरी पालकों के लिए बरदान हैं ये मोबाइल ऐप, जानिए कैसे

भोपाल।

ग्रामीण इलाकों में खेती-बाड़ी के साथ-साथ कई किसान पशुपालन का रोजगार भी बड़े पैमाने पर करने लगे हैं। ऐसे में बकरी पालन का रोजगार पशुपालकों द्वारा ख़ास तौर पर किया जाता है। इसके दो फायदे हैं एक तो बकरी पालन में लागत और देखभाल दोनों ना के बराबर लगती है, तो वहीं बकरी का मांस भी आज के समय में मुनाफे का सौदा है।

बकरी पालन का मुख्य कारण यह भी है कि छोटे और सीमांत किसान जो खेती के साथ-साथ गाय-भैंस का पालन नहीं कर सकते हैं, वो बकरी पालन का रोजगार कर अच्छा मुनाफा कम रहे हैं। वहीं सरकार भी इस रोजगार को बढ़ावा देते हुए जरुरतमंद किसानों को बकरी पालन के लिए सब्सिडी भी मुहैया करवा रही है।

इन तमाम सुविधाओं के बावजूद जो एक बड़ी समस्या किसानों के सामने आ रही है वो यह है कि उन्हें उन्नत जानकारी के बारे में समय रहते पता नहीं चल पाता है। ऐसे में जो किसान उन्नत बकरी पालन का रोजगार करना चाहते हैं, वो इन 5 ऐप की मदद से बकरी पालन से जुड़ी सभी जानकारी पा सकते हैं।

गोट फार्मिंग ऐप

गोट फार्मिंग मोबाइल ऐप जिसको केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। बकरी पालन रोजगार को सफल बनाने और अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए यह मोबाइल एप्प चार अलग भाषाओं में उपलब्ध है: हिंदी, तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी। इस मोबाइल ऐप पर किसान और पशुपालक भारतीय बकरी की उन्नत नस्ल, उनके प्रजनन प्रबंधन, बकरी के आयु के अनुसार बकरी का खुराख और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस ऐप पर उपलब्ध है।

गोट ब्रीड मोबाइल ऐप

गोट ब्रीड मोबाइल ऐप दरअसल बकरियों के नस्ल के बारे में जानकारी देता है। अगर कोई भी किसान बकरी की उन्नत नस्लों के बारे में जानना चाहते हैं तो वह इस एप्प को डाउनलोड कर सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह मोबाइल एप्प हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में उपलब्ध है।

बकरी उत्पाद मोबाइल ऐप

बकरी उत्पाद मोबाइल ऐप जैसा की आप नाम से समझ पा रहे होंगे यह बकरी से जुड़े उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी किसानों को मुहैया करवाता है। इसमें ना सिफ़्र बकरी के बारे में बल्कि बकरी से जुड़े उत्पाद जैसे बकरी के मांस और दूध का मूल्य, उत्पाद और उनकी पोषण संबंधी जानकारी दी गई है। यह मोबाइल ऐप हिंदी, तमिल, कन्नड़ भाषा में उपलब्ध है।

बकरी गर्भाधान सेतू मोबाइल ऐप

बकरी गर्भाधान सेतू मोबाइल ऐप बकरियों के कृत्रिम गर्भाधान के बारे में सपूर्ण और सुरक्षित जानकारी किसानों को देता है। आज के समय में कृत्रिम गभाधज़न की तकनीक से बकरियों की नस्ल में सुधार किया जा सकता है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप बकरियों के कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक से लेकर उसके फायदे के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बकरी मित्र ऐप

भारतीय कृषि अनुसंधान के केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान और अंतरराष्ट्रीय पशुधन शोध संस्थान नैरोबी केन्या के द्वारा बकरी मित्र ऐप को विकसित किया है। यह ऐप खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के किसानों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इस मोबाइल ऐप पर भी बकरी से जुड़ी सभी जानकारी जैसे बकरी के उन्नत नस्लों की जानकारी, प्रजनन से जुड़ी जानकारी और अन्य जानकारी यहां उपलब्ध है, क्योंकि इस ऐप को ICAR – CIRG ने विकसित किया है तो किसानों को वह सभी जानकारी भी इस ऐप से मिलती है, जो संस्थान की ओर से चलाया जा रहा है। किसानों को प्रशिक्षण व कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप में संस्थान का फोन नंबर भी है, जिसके जरिये आप विशेषज्ञ से सीधा बात कर सकते हैं।

होम्योपैथिक औषधि जो गर्मी से पशुओं की सुरक्षा करेगी और दूध की मात्रा भी बढ़ाएगी

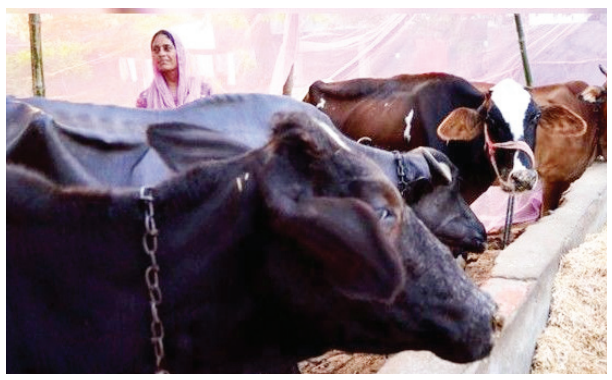

भोपाल। भीषण गर्मी से पशुओं को बचाना है तो करें इन होम्योपैथिक औषधि का इस्तेमाल, होगी दूध में भी बढ़ोत्तरी जैसे ही ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, तो पशुओं में भी कई बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसका मुख्य कारण मौसम में हो रहा बदलाव है। बदलते मौसम के दौरान पशुओं में बुखार, बेचैनी, श्वास की तकलीफ़ हांफना (हौकनी), आँखों व नथुनों से पानी आने के लक्षण दिखाई देते हैं। पशुओं को अत्यधिक गर्मी होने के कारण बुखार, बेचैनी, श्वास की तकलीफ़ हांफना (हौकनी), आँखों व नथुनों से पानी आने जैसे लक्षणों का निवारण करने हेतु इन होम्योपैथिक औषधियों का उपयोग आप अपने पशुओं पर कर सकते हैं।

- प्रेवेंटो (ग्रीष्म प्रकोप से बचने हेतु)
- पायरोसुल (बुखार से राहत दिलाने हेतु)
- प्रीवेंटो + पायरोसूल के द्वारा करें ग्रीष्म प्रकोप पर डबल अटैक
- अपने पालतू पशुओं में गर्मी के कारण होने वाली बीमारी से बचाने और उसको बढ़ने से रोकने के लिए आप कुछ सरल कदम उठा सकते हैं:
- सुनिश्चित करें की पशुओं के आस-पास हर समय भरपूर मात्रा में ताजा, ठंडा पानी उपलब्ध हो।
- जितना हो सके पशुओं को वातानुकूलित या हवादार क्षेत्रों में रखें।
- सुनिश्चित करें कि पशुओं के पास स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए जगह हो।
- दिन में दो बार पशु को ठन्डे पानी से नहलाएं।
- आवश्यकता पड़ने पर पशु चिकित्सक की सलाह लें।
- थोड़ी सी देखभाल से आप अपनी पशुओं को पूरी गर्मी में स्वस्थ और आरामदायक रहने में मदद कर सकते हैं।
- प्रीवेंटो + पायरोसूल के द्वारा करें ग्रीष्म प्रकोप पर डबल अटैक
- जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, पशुओं को गर्म मौसम में होने वाली बीमारियों का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए आपके पशुओं को अत्यधिक गर्मी के कारण होने वाले बुखार, बेचैनी, श्वास की तकलीफ़ हाफ्ना, आँखों व नथूनों से पानी आने जैसे लक्षणों का निवारण करने हेतु गोयल वेट फार्मा लेकर आया है – प्रीवेंटो+पायरोसूल होम्योपैथिक पशु औषधि। इन दवाओं के इस्तेमाल से आपके पशुओं की समस्या जल्द ठीक हो जाएगी तथा पशु का दूध भी कम नहीं होगा। यह दवा कुछ इस प्रकार है- प्रीवेंटो + पायरोसूल का कॉम्बो! यह मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है।
- प्रीवेंटो + पायरोसूल देने की विधि।
- तीव्र ज्वर की स्थिति में
- दोनों दवाओं को आधे-आधे घंटे के अंतर से 6 से 8 बार दें।
- सामान्य स्थिति में
- दोनों दवाओं को आधे-आधे घंटे के अंतर से दिन में तीन बार दें।
- पशु को दवा रोटी, गुड़, अथवा जीभ पर भी दे सकते हैं।
- अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह लें।

किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए सरकार देगी 5 लाख तक की सब्सिडी

नई दिल्ली। देश के किसानों की आर्थिक हालत और बेहतर हो सके और खेती के दौरान उनकी परेशानियां कम हों, इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाओं पर काम कर रही है। इसी के तहत अब केंद्र सरकार कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने कि लिए 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है।

देश में किसानों की आय बढ़ाने एवं कृषि की लागत को कम करने के लिए सरकार नई मशीनों, उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी भी उपलब्ध कराती है। अब इन यंत्रों में सरकार ने किसान ड्रोन को भी शामिल कर लिया है। किसान ड्रोन की मदद से किसान आसानी से अपने खेतों में कीटनाशकों एवं खाद का छिड़काव कम समय एवं कम लागत में कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 'किसान ड्रोन को बढ़ावा मुद्दे, चुनौतियां और आगे का रास्ता' विषय पर सम्मेलन का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के व्यापक हित में कृषि कार्यों में ड्रोन के उपयोग की पहल की है। फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों व पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए 'किसान ड्रोन' के उपयोग को सरकार बढ़ावा दे रही है, जिसका बजट में भी प्रावधान किया गया है। देश के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार के एजेंडा में है।

चार लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, सरकार किसानों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने, कृषि लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ड्रोन उपयोग को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए ड्रोन खरीदने में विभिन्न वर्गों को छूट भी प्रदान की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत, महिलाओं और किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए 5 लाख की सब्सिडी दी जा रही हैं, वहीं अन्य किसानों को 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ड्रोन खरीदने में मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति, लघु और सीमांत, महिलाओं एवं पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के लिए, ड्रोन लागत का 50फीसदी अथवा अधिकतम 5 लाख रुपये और अन्य किसानों को 40फीसदी अथवा अधिकतम 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

एसएमएएम योजना के तहत ड्रोन खरीदने के लिए 100फीसदी सब्सिडी

इस प्रौद्योगिकी को किसानों व अन्य कृषि संगठनों के लिए किफायती बनाने के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण व परीक्षण संस्थानों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन की खरीद हेतु लागत के 100फीसदी तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को खेतों पर प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन लागत का 75फीसदी तक की सब्सिडी दी जाएगी। सीएचसी स्थापित करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन की लागत के तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

किसानों को उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज उपलब्ध करने के लिए

एरोपॉनिक विधि से अब किया जाएगा आलू बीज का उत्पादन

भोपाल।

अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उच्च गुणवत्ता के बीज का होना आवश्यक है। अच्छे बीज से जहां फसलों का उत्पादन बढ़ता है वहीं उत्पादकता भी बढ़ती है जिससे किसानों को होने वाले लाभ में भी बढ़ोतरी होती है। किसानों को समय पर प्रमाणित बीज नहीं मिलने के कारण उन्हें साधारण बीज का ही उपयोग करना पड़ता है, जिसके चलते फसल में कई तरह के कीट एवं रोग लग जाते हैं और किसानों को काफी नुकसान होता है। सरकार ने किसानों को आलू के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए नई तकनीक से बीज उत्पादन का फैसला लिया है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं मध्य प्रदेश के उद्यानिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह की उपस्थिति में विषाणु रोग रहित आलू बीज उत्पादन के लिए एरोपॉनिक विधि का मप्र सरकार के साथ दिल्ली में अनुबंध हुआ। इसके अंतर्गत ग्वालियर में मप्र की पहली लैब स्थापित होगी। अनुबंध के कायक्रम के अवसर पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि किसानों को फसलों के प्रमाणित बीज समय पर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ने हवा में आलू के बीज उत्पादन की यह अनूठी तकनीक विकसित की है। यह बीज आलू के फसल को विषाणु प्रतिरोधक बनाया गया है। जिससे विषाणु जड़ति रोग का असर न पड़े। आलू के बीज की मांग अधिक रहने के कारण इसके बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने अन्य कृषि विश्वविद्यालय से अनुबंध किया है।

एरोपॉनिक के जरिये पोषक तत्वों का छिड़काव मिस्टिंग के रूप में जड़ों में किया जाता है। पौधे का ऊपरी भाग खुली हवा व प्रकाश में रहता है। एक पौधे से औसत 35-60 मिनिकन्द (3-10 ग्राम) प्राप्त किए जाते हैं। चूंकि, मिट्टी उपयोग नहीं होती तो मिट्टी से जुड़े रोग नहीं होते। पारंपरिक प्रणाली की तुलना में एरोपॉनिक प्रजनक बीज के विकास में दो साल की बचत करती है।

राज्य में 4 लाख टन आलू बीज की आवश्यकता है

राज्य में आलू के अधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए राज्य को जरूरत के अनुसार बीज की पूर्ति कम है। राज्य में लगभग 4 लाख टन आलू बीज की जरूरत है। जिसे 10 लाख मिनी ट्यूबर उत्पादन क्षमता वाली इस तकनीक से पूरा किया जाएगा का आश्वासन कृषि राज्य मंत्री ने दिया है। ग्वालियर में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आलू फसल का चयन किया गया है।

मध्यप्रदेश के इन जिलों में होता है आलू का उत्पादन

इस मौके पर मध्यप्रदेश के कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि देश भर में आलू के उत्पादन में मध्य प्रदेश छठा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य में मालवा क्षेत्र आलू के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य में इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, भोपाल, सीधी, सतना, रीवा, सरगुजा, राजगढ़, सागर, दमोह, छिंदवाडा, जबलपुर, पन्ना, मुरैना, छतरपुर, विदिशा, रतलाम एवं बैतूल हैं।

11 तक इजरायल के दौरे पर रहें केंद्रीय कृषि मंत्री

भोपाल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 11 मई तक इजराइल यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान श्री तोमर कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थानों का दौरा करेंगे तथा कृषि क्षेत्र में भी जाएंगे। श्री तोमर वहां के मंत्री एवं प्रमुख लोगों के साथ बैठक करेंगे तथा कृषि से संबंधित स्टार्टअप कंपनियों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल होंगे। श्री तोमर 9 मई को सुबह इजराइल में ग्रीनहाउस एग्रीकल्चर एरिया का दौरा करेंगे। तत्पश्चात, वहां नेटफिम क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, जहां गन्ना व कपास के अलावा धान की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई के उपयोग सहित सूक्ष्म और स्मार्ट सिंचाई प्रणाली अपनाई जा रही है। अपरान्ह में श्री तोमर इजराइल निर्यात एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग संस्थान का दौरा करेंगे तथा शाम को इजराइली एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनियों के साथ गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)